been paid Rs. 78.05 crores as compensation which includes an element of rehabilitation grant if Rs. 32.38 crores as admissible under Rule 94.

(b) Rs. 32·38 crores upto the end of February, 1958. This amount includes payment by cash/by purchase of property/and by adjustment of public dues.

(c) Yes, only persons entitled under Rule 94 and 96.

Shiva Rao Committee

*1841. **Shaikh Mohammad Akbar:** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether it was one of the recommendations of the Shiva Rao Committee that every State after decentralisation of the Employment Exchanges had to confirm 60 per cent. of the staff transferred to them from the Centre; and

(b) if so, whether the Punjab Government have complied with the above recommendation?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): (a) No.

(b) Does not arise.

Rehabilitation Grants

*1849. **Pandit Thakur Das Bhargava:** Will the Minister of **Rehabilitation and Minority Affairs** be pleased to state whether any rehabilitation grants or any compensation in lieu of these grants have been paid to persons entitled to them apart from persons entitled to such grants under rule 96 of the Displaced Persons Compensation and Rehabilitation Rules, 1955?

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri P. S. Naskar): Every person having a verified claim of less than Rs. 50,000 is entitled to a rehabilitation grants under Rule 94 in accordance with the scale laid down in the rules. Upto 28th February, 1958, 2,89,479 persons have been paid Rs. 78.50 crores as compensation which includes an element of rehabilitation grants of Rs. 32.38 crores.

कुटीर तथा लघु उद्योग

२७४८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर तथा लघु उद्योगों की किन किन फर्मों के नाम १९५६-५७ में सम्भरण और निबटान महानिदेशक की स्वीकृत ठेकेदारों की सूची में लिखे गये ;

(ख) उक्त वर्ष में उपरोक्त फर्मों के अतिरिक्त कितनी फर्मों ने इस सूची में अपना नाम सम्मिलित करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ; और

(ग) जिन फर्मों के नाम स्वीकृत ठेकेदारों की सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं, उन्होंने किस प्रकार की वस्तुएं दीं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) ऐसी फर्मों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६**]

(ख) ७१ ।

(ग) सूची सभा पटल पर रख दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६**]

रबड़ के जूते

२७४९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबड़ के जूते बनाने वाले कारखानों के विस्तार के लिये जो लाइसेंस दिये गये हैं, उनके फलस्वरूप इनके विस्तार में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १७**]